गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

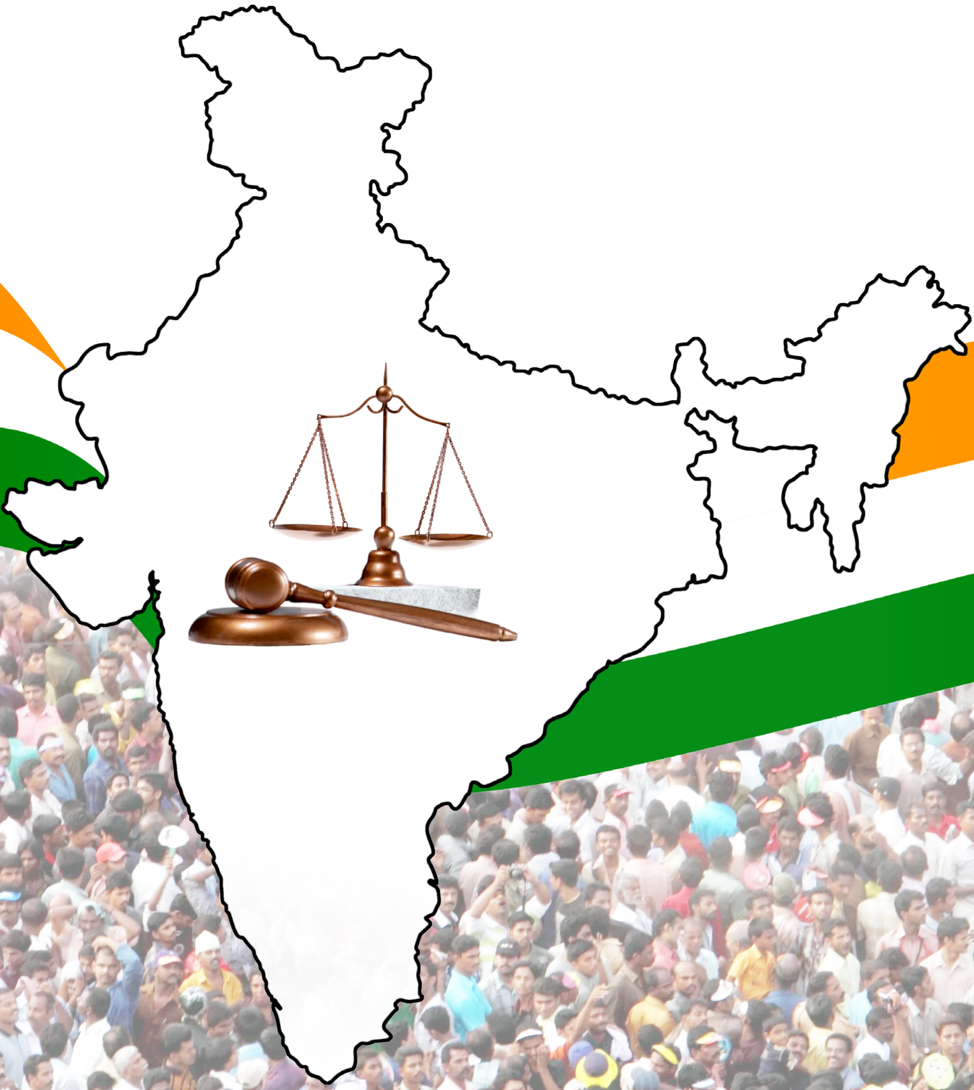

Investigation & Trial Framework in Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

BPRD

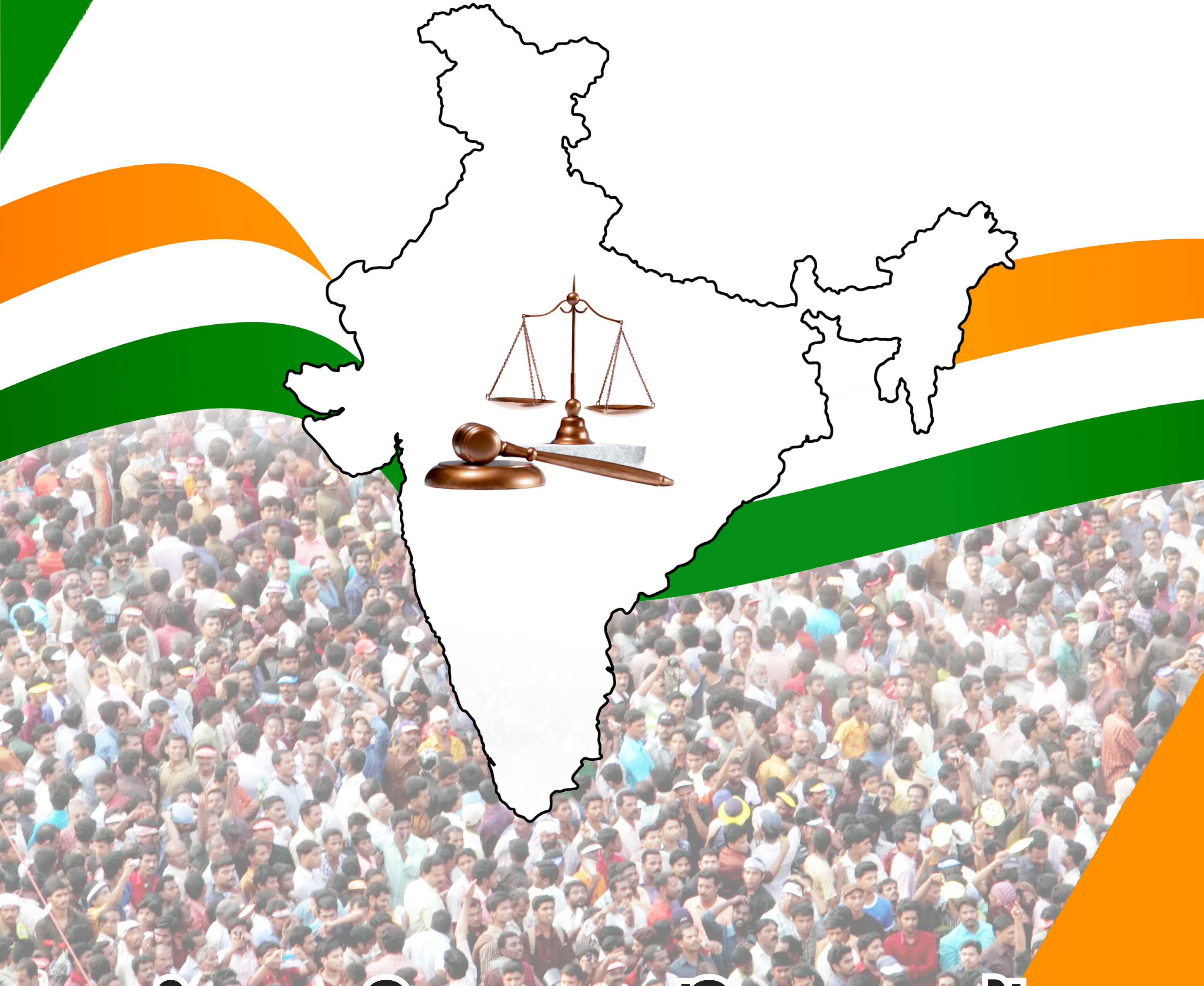

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में समय सीमा के तहत जाँच और ट्रायल फ्रेमवर्क

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Transformative Judicial Reforms

Key Features

1. Overview:

- BNSS introduces a comprehensive timeline for every stage of criminal proceedings, creating a structured framework for legal processes.

2. FIR Registration:

- FIR to be recorded within three days for complaints submitted through electronic communication, expediting the initial phase of criminal cases.

3. Medical Examination Reports:

- Medical examination reports of rape victims to be forwarded within seven days to the investigating officer, ensuring timely collection of crucial evidence.

4. Victim/Informant Updates:

- Regular updates to victims/informants about status of investigation within 90 days, fostering transparency and keeping stakeholders informed.

5. Framing Charges:

- Competent magistrates required to frame charges within 60 days from first hearing on charge.

परिवर्तनकारी न्यायिक सुधार

समयसीमा कार्रवाई की प्रमुख विशेषताएं:

1.अवलोकन:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने क्रिमिनल प्रक्रिया के हर चरण के लिए एक संरचित फ्रेमवर्क बनाते हुए एक संपूर्ण समय सीमा प्रस्तुत की है।

2.एफआईआर पंजीकरण:

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई शिकायतों के लिए एफआईआर को तीन दिन के भीतर दर्ज किया जाएगा, जो की क्रिमिनल मामलों की जाँच को गति देगा।

3.चिकित्सा जांच रिपोर्ट:

बलात्कार पीड़िता के लिए चिकित्सा जांच रिपोर्ट को जांच अधिकारी द्वारा सात दिनों के भीतर आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे समय पर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाया जा सके।

4.पीड़ित / सूचनाकर्ता को अपडेट:

जांच की स्थिति के बारे में पीड़ितों / सूचनाकर्ता को 90 दिन के भीतर नियमित अपडेट सुनिश्चित करते हैं, जो की पारदर्शिता को सुनिश्चित करते है।

5.आरोप /चार्ज फ्रेमिंग:

सक्षम मजिस्ट्रेट्स के लिए आवश्यक है कि वो आरोप पर पहली सुवनाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करें।

6. Trial in Absentia:

- Courts empowered to initiate trial in absentia against proclaimed offenders after 90 days from charge framing, expediting proceedings and ensuring timely delivery of justice to victims and society.

7. Judgment Pronouncement:

- Criminal court to pronounce judgments within 45 days post the trial's conclusion, ensuring a prompt legal resolution.

8. Uploading of Judgment:

- Criminal court to upload judgment within seven days from the date of pronouncement on their portal, providing easy access to litigants.

Benefits of Timeline Implementation

Swift Justice:

- Expedited criminal proceedings ensure timely resolution, reducing the burden on the legal system.

Transparency:

- Regular updates to victims and stakeholders foster a transparent legal process, promoting public trust.

Efficiency:

- Streamlined timelines enhance the efficiency of legal proceedings, minimising delays.

6.ट्रायल इन एबसेंटिया:

अदालतों को आरोप तय होने के 90 दिनों के बाद घोषित अपराधियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करने, कार्यवाही में तेजी लाने और पीड़िता को समय पर न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया।

7.निर्णय / फैसला घोषणा:

अपराधिक न्यायालय को अदालत में ट्रायल समापन के 45 दिनों के भीतर निर्णय घोषित करना सुनिश्चित करता है।

8.जजमेंट की कॉपी अपलोड करना:

आपराधिक न्यायालय को फैसले की तारीख से सात दिनों के भीतर अपने पोर्टल पर जजमेंट की कॉपी अपलोड करना होगा, जिससे वादियों को आसानी से कॉपी मिल सके।

समय सीमा कार्रवाई के लाभ

त्वरित न्याय:

न्यायिक प्रक्रियाएं का समय समाप्त होने से , कानूनी प्रणाली पर बोझ कम होता है ।

पारदर्शिता:

पीड़ितों और हितधारिताओं को नियामकों की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट, सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देते हैं।

कुशलता:

संघटित समयसीमा कार्रवाई कानूनी प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाती है जो कि देरी को कम करती है।